Major Decision by the Government of India in the Interest of Farmers

Natural Gas Supply for Fertilizer Production Included in Government's Priority List

Urea Stock Significantly Higher than Last Year Ahead of the Kharif Season

Posted On: 10 MAR 2026 7:12PM by PIB Delhi

The Government of India has issued the **Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026**, officially including the fertilizer sector in its priority list. To ensure that domestic fertilizer production remains unaffected, fertilizer plants have been categorized under **'Priority Sector-2'** for natural gas supply.

Under this new mandate:

- Fertilizer plants will be provided with at least **70%** of their average natural gas consumption based on the last six months.
- This measure aims to safeguard fertilizer production against global supply chain disruptions, particularly the LNG supply issues caused by the ongoing conflict in the Middle East.
- The priority status ensures that farmers receive fertilizers on time, allowing agricultural activities to continue smoothly despite the global gas crisis.

By prioritizing natural gas for fertilizer production, the Government of India has reaffirmed that meeting the needs of farmers is one of its highest priorities. Proactive preparations have been initiated to ensure that political instability in West Asia does not adversely impact the upcoming Kharif sowing season in India.

High-Level Meeting at Department of Fertilizers Mobilizes Industry Leaders and Petroleum Ministry

A high-level meeting was held in the Department of Fertilizers on Tuesday regarding this matter. High-ranking officials from all fertilizer companies participated in the meeting and presented a detailed account of their preparations and challenges to the Department. On behalf of the Department, all companies were instructed that every possible effort is being made to keep fertilizer plants running continuously. Senior officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas also attended this meeting.

Click here to see Gazette

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270784
CG-DL-E-10032026-270784

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947
No. 1180] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1232(अ).— केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप होरमुज जलडमरूमध्य के माध्यम से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस शिपमेंट में व्यवधान हुआ है और आपूर्तिकर्ताओं ने अपरिहार्य घटना खण्ड लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एवं अन्य बनाम भारत संघ (2001 का विशेष संदर्भ संख्या 1) के सामान्य निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है ;

और, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की अनुसूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं ;

और, केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण तथा उससे संबंधित व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि उसकी राय में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने के लिए अथवा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ;

और, प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत पुनः गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, घरेलू पीएनजी आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, उर्वरक उत्पादन, एलपीजी उत्पादन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है ;

और, केंद्रीय सरकार, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस का समान वितरण और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और पुनः गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, की प्राकृतिक गैस आपूर्ति के उत्पादन, क्षेत्रवार आवंटन और उपयोजन, के वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग को विनियमित करना आवश्यक समझती है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की उपधारा (2) के खंड (घ) और (च) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन**--केंद्रीय सरकार, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और समान वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश दे सकेगी :--

(1) प्राथमिकता क्षेत्र 1

निम्न क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता आवंटन समझा जाएगा और इसे, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के सौ प्रतिशत तक बनाए रखा जाएगा :

(क) घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस आपूर्ति ;

(ख) परिवहन के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस ;

(ग) एलपीजी उत्पादन, जिसके अंतर्गत एलपीजी संकोचन अपेक्षाएं भी हैं ;

(घ) पाइपलाइन संपीडित ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन अपेक्षाएं ।

(2) प्राथमिकता क्षेत्र 2

उर्वरक प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के सत्तर प्रतिशत तक सुनिश्चित की जाएगी :

परंतु इकाइयाँ उर्वरकों के उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए गैस आपूर्ति का उपयोग नहीं करेंगी और इस आशय का प्रमाणपत्र उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पीपीएसी" कहा गया है) को प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट इकाई को दिया गया आवंटन किसी अन्य इकाई को नहीं किया जा सकेगा ।

(3) प्राथमिकता क्षेत्र 3

गैस विपणन अस्तित्व यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से चाय उद्योग, उत्पादन और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के अस्सी प्रतिशत पर बनाए रखी जाती है :

(घ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालक, और

(ङ) शहरी गैस वितरण अस्तित्व,

इस आदेश में अंतर्विष्ट निर्देशों का, गेल के समन्वय से, तत्काल अनुपालन करेंगे, जिसमें आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन, आपूर्ति का परिवर्तन और प्राकृतिक गैस का क्षेत्रवार ऐसा आबंटन सम्मिलित है, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए ।

6. विद्यमान संविदा संबंधी व्यवस्थाओं पर अध्यारोही प्रभाव—इस आदेश के उपबंधों का, गैस विक्रय करारों (जीएसए) और अन्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

7. सूचना प्रस्तुत करना-- प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और पुन: गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, का प्रत्येक उत्पादक, आयातक, परिवहनकर्ता, विपणक या वितरक, उत्पादक, आयात, स्टॉक, आबंटन, आपूर्ति और उपभोग से संबंधित सूचना, केंद्रीय सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को देगा ।

स्पष्टीकरण--*सूचना* देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, पीपीएसी को नोडल अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत अधिकृत करती है ।

[फा. सं. 16016/6/2026-जीपी1 (ई:55648)]
रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1232(E).— Whereas, the Central Government has assessed that the ongoing conflict in the Middle East has resulted in the disruption of liquefied natural gas shipments through the Strait of Hormuz and suppliers have invoked force majeure clause which would entail diversion of natural gas to the priority sectors;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court in the common judgement of Association of Natural Gas and others v. Union of India (In re Special Reference No. 1 of 2001) has held that natural gas and liquified natural gas come within the purview of petroleum and petroleum products;

And Whereas, the petroleum and petroleum products are covered under entry 5 of the Schedule of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

And Whereas, the Central Government is conferred with the power under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, to regulate, *inter alia*, the supply and distribution of petroleum and petroleum products, as well as trade and commerce relating to the same, if it is of the opinion that it is necessary or expedient to do so for maintaining or increasing supplies of petroleum and petroleum product or for securing their equitable distribution;

And Whereas, natural gas, including re-gasified LNG are a critical input for sectors such as domestic PNG supply, CNG for transport, fertilizer production, LPG production and other industrial activities;

And Whereas, the Central Government, in order to ensure equitable distribution and continued availability of natural gas for priority sectors, considers it necessary to regulate production, sector-wise allocation and diversion of natural gas supplies, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of natural gas, including LNG and re-gassified-LNG.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 read with clauses (d) and (f) of sub-section (2) of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby makes the following order, namely: —

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Regulation of production, supply and distribution. – The Central Government may, with a view to maintain supplies and securing equitable distribution and availability of natural gas for priority sector, hereby directs as under: -

(1) Priority Sector I

The supply of natural gas to the following sectors shall be treated as priority allocation and shall be maintained subject to operational availability to hundred per cent. of their average past six month average gas consumption:

(a) Domestic Piped Natural Gas supply;

(b) Compressed Natural Gas for transport;

(c) LPG production including LPG shrinkage requirements;

(d) Pipeline compressor fuel and other essential pipeline operational requirements.

(2) Priority Sector II

The supply of natural gas to the fertilizer plants shall ensure seventy per cent. of their past six month average gas consumption, subject to operational availability:

Provided that the units shall not use the gas supply for any other purpose except in the production of fertilizers and a certificate to this effect shall be furnished to the Petroleum Planning and Analysis Cell (hereinafter referred to as the "PPAC") through the Ministry of Fertilizer:

Provided further that allocation to a particular unit may not be diverted to any other unit.

(3) Priority Sector III

The gas marketing entities shall ensure that gas supply to tea industries, manufacturing and other industrial consumers supplied through the national gas grid is maintained at eighty per cent. of their past six month average gas consumption subject to operational availability.

Explanation.- For the purpose of gas allocation to this sector, the principles shall be evolved by the PPAC in coordination with the Industry Committee.

(4) Priority Sector IV

All City Gas Distribution (hereinafter referred to the "CGD") entities shall ensure that industrial and commercial consumers supplied through their networks receive eighty per cent. of their past six month average gas consumption subject to operational availability.

Explanation : For the purpose of gas allocation to this sector, the principles shall be evolved by the PPAC in coordination with the Industry Committee.

3. Gas redistribution. - (1) The gas required to meet the priorities mentioned in paragraph 2 shall be through full or partial curtailment of gas supplied in the following order of priority:

(a) petrochemical facilities not limited to:

(i) ONGC Petrol additions Limited;

(ii) GAIL Pata Petrochemical Complex;

(iii) Reliance O2C and other High-Pressure High Temperature (HPHT) gas consumers;

(b) power plants as required.

(2) The oil refining companies shall absorb the impact of LNG supply disruption to the extent feasible by reducing gas allocation to refineries to approximately sixty-five per cent. of the past six month gas consumption, subject to operational feasibility.

4. Implementation mechanism of pooling of gas. - (1) The Gas Authority of India Limited (hereinafter referred to as the GAIL), in coordination with the PPAC shall manage the supplies of natural gas to implement the above directions for which it shall submit the invoice price of every diverted volume of natural gas to the PPAC.

Robust Fertilizer Reserves and Buffer Stock

The Department of Fertilizers has assured farmers that despite disruptions in maritime transport and cargo ship movements, India maintains a sufficient inventory of fertilizers. To eliminate any confusion, the Department has released the following data-backed status of current reserves:

- An aggressive strategy of advance stocking during low-consumption phases has resulted in a massive buffer stock.

- Ahead of the Kharif season, India's total fertilizer reserve has reached **180.12 Lakh Metric Tons (LMT)**.
- This represents a **36.6% increase** compared to the **131.79 LMT** recorded during the same period last year (March 10, 2025).
- This surge is primarily driven by an unprecedented increase in critical soil nutrients, specifically **DAP (25.17 LMT)** and **NPKS (56.30 LMT)**.

Comparative Stock Status (As of March 10, 2026, in LMT):

Fertilizer	Stock Status (10.03.2026)	Stock Status (10.03.2025)
Urea	61.51	50.90
DAP	25.17	11.55
NPK	56.30	32.29
MOP	12.90	14.41
SSP	24.24	22.64
Total	**180.12**	**131.79**

Ensuring Domestic Availability

The availability of Urea, the most consumed fertilizer in the country, has risen to **61.51 LMT**. This data-backed, robust inventory clearly demonstrates that India is well-insulated from global supply chain shocks for the upcoming Kharif sowing. These strategic reserves ensure that international logistics bottlenecks do not lead to domestic shortages for farmers.

To maintain a continuous supply of all categories of subsidized fertilizers, the Department of Fertilizers has already managed essential shipments. As of February 2026, the Government of India has imported **98 LMT** of Urea, with an additional **17 LMT** scheduled in the pipeline for the next three months. This proactive approach serves as a testament to the government's commitment to protecting the interests of the farming community amidst global turmoil.

***

Neeraj Kumar Bhatt/ Gaurav Kumar Pandey
cmc.fertilizers[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2237803) Visitor Counter : 506
Read this release in: हिन्दी , Marathi , Gujarati , Telugu , Kannada , Malayalam